



युवाओं के सपने हो रहे साकार सारथी बन रही झारखण्ड सरकार

मुख्यमंत्री सारथी योजना अंतर्गत बिरसा योजना

(Block Level Institute for Rural Skill Acquisition)
एवं रोजगार प्रोत्साहन भत्ता/परिवहन भत्ता वितरण का
शुभारंभ

मुख्य अतिथि

श्री हेमन्त सोरेन

माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड

विशिष्ट अतिथि

श्री आलमगीर आलम

माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, पंचायती
राज एवं संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार

श्री सत्यानंद भोक्ता

माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण
एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार

गरिमामयी उपस्थिति

डॉ महुआ माजी

माननीया सांसद, राज्यसभा

श्री संजय सेठ

माननीय सांसद, लोकसभा, रांची

श्री सी. पी. सिंह

माननीय विधायक, रांची

दिनांक : 22 जुलाई, 2023 | समय: अपराह्न 1 बजे

स्थान : आर्यभट्ट सभागार, रांची विश्वविद्यालय

योजना हेतु पात्रता (आयु)-

- सामान्य वर्ग: 18-35 वर्ष
- एससी/एसटी/ओबीसी वर्ग: 18-50 वर्ष तक

बिरसा केंद्र-

- प्रथम चरण में 80 प्रखण्डों में केंद्र की शुरुआत
- प्रखण्ड स्तर पर नि:शुल्क कौशल प्रशिक्षण की व्यवस्था

रोजगार प्रोत्साहन भत्ता-

- युवकों को ₹1,000 प्रतिमाह
- युवतियों/दिव्यांग/परलैंगिक को ₹1,500 प्रतिमाह
(प्रशिक्षण के बाद सफल प्रशिक्षणार्थियों को तीन माह के अंदर नियोजन नहीं होने की स्थिति में भत्ता अधिकतम एक वर्ष के लिए DBA के जरिए)

परिवहन भत्ता-

- ₹1,000 प्रतिमाह
(गैर-आवासीय प्रशिक्षण के प्रशिक्षणार्थियों को उनके घर से प्रशिक्षण केंद्र आने-जाने के लिये भत्ता DBA के जरिए)

टोल फ्री नम्बर: 1800-123-3444

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार



को लाल किले से अपना पहला भाषण दिया था, तब भी इस योजना का एलान किया गया था। प्रधानमंत्री अपने हर भाषण में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर जोर देते हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून 2016 को पुणे में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स लॉन्च किया। इसके तहत 'स्मार्ट सिटी चैलेंज कॉम्पिटिशन' के पहले फेज के लिए चुने गए 20 शहरों में इस योजना की शुरुआत कर दी गई। इस योजना में 48 हजार करोड़ का निवेश होगा। हालांकि पूरा खर्च एक लाख करोड़ रुपये होगा। आधा पैसा राज्य सरकार को देना होगा।

आइए जानते हैं क्या है स्मार्ट सिटी और इससे जुड़ी खास बातें : स्मार्ट सिटी की सबसे खास बात होगी बाधारहित जीवन। इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रमुख आधार होगी यानि इसके जरिए काम में तेजी आएगी और लोगों के जरूरत की चीजें उन्हें आसानी से मिल जाएगी। सरकार का कहना है कि स्मार्ट सिटी में सप्लाई और डिमांड पूरी तरह से मार्केट पर आधारित होगी। इससे जनता, कारोबारी और सरकार सबको फायदा होगा। जानिए कहां से आया स्मार्ट सिटी का कांसेप्ट: स्मार्ट सिटी का कांसेप्ट आर्थिक मंदी के समय सामने आया। 2008 में आईबीएम ने स्मार्ट सिटी का कांसेप्ट पर काम करना शुरू किया। 2009 में कई देशों ने इसे अपना लिया। दक्षिण कोरिया, यूएई और चीन ने इस पर काम शुरू किया और रिसर्च पर काफी पैसा खर्च किया। वर्तमान में वियना, एम्स्टर्डम, लियोन,वेरोन और सिओल के पास सोंगोदे ऐसे ही शहर हैं।

देश की पहली नई स्मार्ट सिटी गुजरात में बनाई जा रही है। इसका नाम गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टैक सिटी(गिफ्ट) है। यहाँ पर 886 एकड़ जमीन पर 110 टावर बनाए जा रहे हैं। यह शहर साबरमती नदी के किनारे बसाया जा रहा है। इस सिटी में डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम से सभी घर एयर कंडीशन युक्त होंगे। पानी को सप्लाई भी इसी तरह से की जाएगी। घरों से कचरा इकट्ठा करने के लिए भी ऑटोमैटिक सुविधा होगी। इस सिटी की अन्य खासियतों में इंटेलिजेंट बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम(आईबीएमएस) , सीसीटीवी कैमरे और सिंक्लास सिस्टम शामिल है। इस शहर में प्रवेश स्मार्ट कार्ड के जरिए ही हो पाएगा। आईबीएमएस के जरिए सभी घरों को लाइटिंग, वॉटिलेशन, और फिल्म की टिकट बुक करने जैसी सुविधा भी मिलेगी। यहाँ पर इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। साथ ही मेट्रो और बीआरटीएस सुविधा भी होगी।

स्मार्ट सिटी के अलग-अलग पैमाने होते हैं। मार्च 2015 में फॉक्स ने टॉप पांच स्मार्ट शहरों की लिस्ट जारी की थी। इनमें स्पेन का बार्सिलोना टॉप पर था। यह शहर पर्यावरण और पार्किंग के मामले में टॉप पर है। अमेरिका का न्यूयॉर्क स्मार्ट ट्रेफिक मैनेजमेंट, लंदन टेक्नोलॉजी व ओपन डाटा, फ्रांस का नाइस शहर पर्यावरण और सिंगापुर टेक्नोलॉजी के प्रयोग व ट्रेफिक मैनेजमेंट में अग्रणी रहा।

रांची का चयन भी स्मार्ट सिटी के लिए किया गया है।

राजधानी रांची का चयन भी स्मार्ट सिटी के लिए किया गया है। रांची के एचईसी परिसर में निर्माण कार्य चल रहा है।

दुनिया के स्मार्ट सिटी

चमचमाती, चौड़ी-चौड़ी सड़कें, साफ-सुथरी गलियां, कायदे से बनी इमारतें, ये है स्मार्ट सिटी। लेकिन एक शहर का स्मार्ट सिटी बनना इतना आसान भी नहीं है। सिर्फ साफ-सफाई के दम पर कोई सिटी स्मार्ट सिटी नहीं बनती। बल्कि स्मार्ट बनने के लिए उसे कई कसौटियों पर खरा उतरना पड़ता है। इन कसौटियों के बारे में बताने से पहले आपको बताते हैं दुनिया की पांच बेहतरीन स्मार्ट सिटी-

स्मार्ट सिटी की लिस्ट में पहले पायदान पर है बार्सिलोना : स्पेन का शहर जिसकी आबादी 16 लाख से ज्यादा है। महात्तूर यूरोपियन फुटबॉल क्लब एफसी बार्सिलोना का शहर।

स्मार्ट सिटी की लिस्ट में दूसरी पायदान पर है न्यूयॉर्क: अमेरिका का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का शहर। यहीं पर संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय भी है।

तीसरी स्मार्ट सिटी है लंदन: ब्रिटेन की राजधानी। यूरोप का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर। ब्रिटिश राजशाही और यूरोपियन शैली की शानदार इमारतों का शहर।

चौथे नंबर पर है फ्रांस का शहर नीस: पहाड़ों के साये में बसे इस शहर की खूबसूरती के चलते ही इसे नीस कहा जाता है।

पांचवीं स्मार्ट सिटी है सिंगापुर: पांच स्मार्ट सिटी की लिस्ट में एशिया का इकलौता शहर, दुनिया के सबसे बड़े कारोबारी शहरों में सिंगापुर की गिनती होती है। आखिर इन शहरों में ऐसा क्या खास है जो इन्हें दुनिया के हजारों शहर से अलग बनाता है। वो क्या सुविधाएँ हैं जिनके आधार पर इन शहरों को दुनिया की बेस्ट सिटी का दर्जा दिया गया है। सिर्फ आर्थिक विकास और आसमान छूती इमारतों की वजह से कोई शहर स्मार्ट नहीं बनता, बल्कि कई कसौटियों पर खरा उतरने के बाद इन शहरों को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला।

कसौटी स्मार्ट सिटी की

टेक्नोलॉजी : यानी शहर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस हद तक और किसके लिए किया जा रहा है। **बिल्डिंग :** शहर की इमारतें नियम के तहत बनी हैं या नहीं, उनमें जरूरी सुविधाएँ सुलभ हैं या नहीं। **सार्वजनिक सुविधाएँ :** शहर में जनता के लिए सार्वजनिक सुविधाएँ हैं या नहीं, और हैं तो उनका स्तर कैसा है। **सड़क और परिवहन :** शहर में सड़कों का स्तर कितना अच्छा है। सार्वजनिक परिवहन कितना असरदार है और गाड़ियों की आवाजाही के इंतजाम कितने अच्छे हैं। **रोजगार :** शहर में रोजगार के कितने अवसर मौजूद हैं। **जीवन स्तर :** शहर में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर कैसा है। जाहिर है इन तमाम कसौटियों पर परखे जाने के बाद ही एक शहर को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिलता है। स्मार्ट का मतलब किसी शहर की आर्थिक तरक्की या तकनीकी तरक्की कतई नहीं है। बल्कि निवासियों के रहन-सहन का स्तर, उन्हें मिलने वाली सुविधाएँ, टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल जैसी कई चीजें मिलकर एक शहर को स्मार्ट बनाती हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या नरेंद्र मोदी सरकार को स्मार्ट सिटी योजना में शामिल शहरों के इन कसौटियों पर कसा जाएगा। अगर मोदी सरकार दुनिया की इन स्मार्ट सिटी को आधार बनाते हुए स्मार्ट सिटी बनाएगी तो हमारी शहर भी दुनिया के बेहतरीन शहरों को टक्कर देंगे।

तेजी से बढ़ रही जनसंख्या और महानगरों की ओर हो रहे पलायन दोनों कई बड़ी समस्याओं की जड़ है। देश के महानगर लगातार डूब रहे हैं। ट्राफिक, कूड़ा और जल जमाव के शिकार शहर सालों पर समस्या से लड़ते रहते हैं। लेकिन दिल्ली जैसे महानगरों में बढ़ता प्रदूषण और आनुपातिक रूप से सार्वजनिक परिवहन साधनों की कमी तो समस्या का प्रत्यक्ष रूप है। दरअसल, दिल्ली

जैसे शहरों में क्षमता से कई गुना ज्यादा लोग रह रहे हैं। इससे ना तो दिल्ली खुश है ना अपना घर-परिवार छोड़कर यहाँ आने वाले लोग खुश हैं। इससे प्रदूषण बढ़ रहा है, जीवनयापन महंगा और गुणवत्ताविहीन हो रहा है, अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ रहे हैं, भीड़भाड़ के चलते बदलती जीवनशैली कई बीमारियों का कारण बन रही है, ना पीने को साफ पानी उपलब्ध है ना खाने

को शुद्ध-स्वच्छ खाना। करोड़ों लोग खुले में बिकाने वाला धूल से सना खाना खाने को मजबूर हैं। इन तमाम समस्याओं का मूल कारण यह है कि हम समस्या के मूल तक जाना ही नहीं चाहते। यदि महानगरों का बोझ कम करना है और छोटे शहरों का भी समान रूप से विकास करना है तो कुछ बेहद जरूरी कदम उठाने पर ध्यान देना चाहिये।

स्मार्ट सिटी से कितना स्मार्ट हो पाएगा देश



मनोज शर्मा

पहला कदम : छोटे शहरों की ओर ले जाएं उद्योग सबसे पहला कदम औद्योगिक विकास का विकेंद्रीकरण (डीआईडी-डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट) हो सकता है। जब हम डीआईडी की बात करते हैं तो पहली व्यावहारिक समस्या आती है कि कोई भी निर्माण कंपनी उसी जगह अपना कारखाना स्थापित करना चाहती है जहां उसे कच्ची सामग्री (रॉ मटेरियल) आसानी से उपलब्ध हो सके और प्रोडक्ट बनने के बाद उसे कम खर्च में उपभोक्ता तक पहुंचाया जा सके। फिलहाल बेहतर आधारभूत संरचना और ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी की जरूरत के चलते छोटे शहर इसके लिये ज्यादा अनुकूल नहीं माने जाते हैं। ऐसे में डीआईडी की शुरुआत उन उद्योगों से की जा सकती है जिनमें प्रोडक्ट को लाने-ले जाने के लिये ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं होती। ऐसे उद्योगों को अपेक्षाकृत कम विकसित इन्फ्रास्ट्रक्चर वाले स्थानों पर शिफ्ट किया जा सकता है। इनमें टेलिकॉम, बीपीओ आदि जैसे सिंसव सेक्टर को महानगरों से दूर करने में प्राथमिकता दी जानी चाहिये, क्योंकि इनका संचालन छोटे शहरों में भी किया जा सकता है। साथ ही ये उद्योग उन शहरों के राजस्व में भी वृद्धि करेंगे, जिससे वहां भी वे तमाम सुविधाएँ और इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में मदद मिलेगी जो आज नहीं हैं।

पलायन रोकने में मिलेगी मदद

औद्योगिक विकास के विकेंद्रीकरण से दो फायदे होंगे। पहला महानगरों का बोझ घटाने के लिये इन उद्योगों के छोटे शहरों में जाने से स्थानीय लोगों के लिये रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी, उन्हें अपना घर-परिवार छोड़कर ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा और संपूर्ण देश का विकास समान गति से करने में मदद मिलेगी। गांवों से सब्जियां, फल आदि जैसे प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को शहरों तक लाने का खर्च और श्रम भी बचेगा क्योंकि उनकी ज्यादा खपत छोटे क्षेत्रों में ही होने लगेगी। उद्योगों के स्थानांतरण के इस कदम के लिये प्रशासनिक तौर पर भी कदम उठाए जा सकते हैं। जैसे छोटे शहरों में उद्योग लगाने पर टैक्स में छूट देना, बड़े शहरों में उद्योग लगाने पर ज्यादा टैक्स वसूलना आदि कारगर हो सकते हैं। वैसे सरकार इस क्षेत्र में मुद्रा बैंक जैसे तमाम नुस्खे आजमा रही है, उम्मीद है आगे भी इस दिशा में प्रयास किए जाते रहेंगे। अब जरूरत है कि उद्यमी वर्ग और आम आदमी इस दिशा में कदम बढ़ाने के प्रयास करें।

शहरी जनसंख्या नियंत्रित हो

इसके बाद लगातार बढ़ रही जनसंख्या भी तमाम समस्याओं की जननी है। इस महासमस्या से निपटने के लिये क्या अब ये जरूरी नहीं कि भारत में भी 'हम दो, हमारे दो' के नारे को कानूनी रूप दे देना चाहिये, ताकि संभवतः करीब 20 साल बाद हमारे पास देश की

लाइट हाउस की गुणवत्ता को लेकर पीएमओ को चिट्ठी

राजधानी रांची के धुर्वा में बन रहे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाइट हाउस प्रोजेक्ट धुर्वा के निमाणाधीन भवन की गुणवत्ता मानकों को लेकर कुछ उपभोक्तों ने प्रधानमंत्री कार्यालय को चिट्ठी लिखकर शिकायत दर्ज करायी है। उन्होंने लिखा है कि महोदय, उपरोक्त विषयक निम्नवत अवगत करना है कि दिनांक 10.07.2023 को लाइट हाउस प्रोजेक्ट धुर्वा रांची झारखंड का निमाणाधीन भवन का खंड ई का एक हिस्सा मध्य रात्रि में पूर्णतः जर्मीदोज हो गया। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार मध्य रात्रि में जोरदार आवाज के साथ यह घटना हुई। उपरोक्त वर्णित बिंदु से हम सभी लाभुकों में संशय की स्थिति बनी हुई है की निमाणाधीन भवन में प्रयोग किया जाने वाला सामग्री उच्च मानक का नहीं है और भविष्य में हम सभी लाभुकों को किसी अनहोनी का शिकार हो सकते हैं। महोदय मकान की गुणवत्ता को 15 दिन के अंदर सार्वजनिक किया जाए ताकि हम सभी लाभुकों को विश्वास हो। जब तक हम सभी लाभुकों को घर नहीं मिल रहा है तब तक बैंक से ब्याज बंद करवाया जाये।

हम सभी लाभुक जिसका बैंक से लोन नहीं हुआ उसका नाम नहीं काटा जाये। लाइट हाउस में इस तरह की घटना हुई है उसको देखने के बाद लग रहा है भविष्य में किसी प्रकार घटना दुर्घटना होगी तो इसकी जिम्मेवारी तय की जाये। लाइट हाउस प्रोजेक्ट रांची के जो भी लाभुक हैं जिन्होंने लोन लिया है उनका ब्याज दर न्यूनतम किया जाये जो अभी बाजार दर पर है। अभी हम लोग जहां भी रह रहे हैं वहां का भाड़ा भी लग रहा है और जो लोन लिये हैं, उसकी किस्त भी लग रही है। घर परिवार को भी देखना है जिसके वजह से हम सभी परेशान हैं, तो जल्द से जल्द हैड ओवर किया जाये ताकि हमारी परेशानी कम हो सके। हम सभी लाभुकों को मूलभूत सुविधा जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाये। हम सभी लाभुकों जिनका बैंक से गृह ऋण है उनके खाते से अनावश्यक राशि अलग-अलग समय में काटी जा रही है, जो गलत है। कृपया हम सभी लाभुकों का जान माल एवं सुरक्षित जिंदगी हेतु संबद्ध अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश देकर अनुग्रहित करें। लाभुकों ने रांची नगर निगम का चेराव भी किया।

जनसंख्या के अनुपात में संसाधन भी उपलब्ध होंगे। बेतहाशा बढ़ती जनसंख्या कई समस्याओं की जड़ है; चाहे वो सड़कों पर दौड़ती भीड़ हो या

सकती है इससे जन्म-मृत्यु दर का अंतर संतुलित होगा अचानक आबादी में युवाओं का अनुपात कम होने



सामना भी नहीं करना पड़ेगा। **मुश्किलों के जाल में युवा आबादी** भले ही हम सीना तानकर आज यह बात कह रहे हैं कि हम विश्व के सबसे युवा देश के निवासी हैं और युवा हमारी ताकत हैं। लेकिन देश की स्थिति देखकर हम यह बात बेहद अच्छे से जानते हैं कि यही युवा

